47 lakhs. They have been rehabilitated in different States and a sum of Rs. 202.44 crores had been spent on their rehabilitation upto the end of 31st March, 1967. The rehabilitation assistance to them covers many fields like rural/urban rehabilitation programmes, housing, employment, compensation, educational and medical facilities, etc. In order to indicate the exact nature of each of the tasks which yet remains to be completed and its approximate quantum, a comprehensive assessment of the total problem and the work already completed in different fields will have to be made. This will mean a detailed review covering the progress of rehabilitation work in different states and in different fields over a period of about 20 years and more. It is felt that it is not possible to list all this information in exact terms in reply to this question in view of the extensive field covered by the question.

It may be stated that the work of rehabilitation of displaced persons from West Pakistan has been almost completed. Information, however, with regard to the residual items of work in respect of them is given *inter alia* in Part II of the Report for the year 1967-68 of the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, Department of Rehabilitation, copies of which have already been circulated to the Members of Parliament and also are available in the library of Parliament. In this matter, particular attention is requested to chapters XIII and XIV of the Report.

बिहार में कृषि की भूमि का उपयोग

1269. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री मान सिंह वर्मा :
श्री एन० के० शेजवालकर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में 425 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि में से केवल 225 लाख एकड़ भूमि कृषि के उपयोग में लाई जा रही है और 200 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बेकार पड़ी हुई भूमि को उपयोग में लाने के लिये कोई योजना तैयार करने का विचार रखती है ?

†[UTILISATION OF AGRICULTURAL LAND IN BIHAR

1269. SHRI J. P. YADAV:
SHRI MAN SINGH VARMA :
SHRI N. K. SHEJWALKAR :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that out of 425 lakh acres of cultivable land in Bihar, only 225 lakh acres of land is being utilised for agriculture and 200 lakh acres of cultivable land is lying unused; and

(b) if so, whether Government propose to prepare a plan for utilisation of the unused lands ?]

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब शिंदे) : (क) और (ख) बिहार सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHEB SHINDE) : (a) and (b) The information is being collected from the Government of Bihar and will be placed on the Table of the Sabha as soon as possible.]

पाकुड़ (बिहार) के पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों को सुविधाएं

1270. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री एन० के० शेजवालकर :
श्री मान सिंह वर्मा :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रम कानूनों के अधीन कुछ उपबन्ध करके पाकुड़ (बिहार) के क्वेरी (पत्थर की खान) में काम कर रहे तीस हजार से ऊपर पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों को खान में काम करने वाले मजदूरों की सी सुख-सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो इन मजदूरों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान करने का विचार है ?

† [ ] English translation.

†[FACILITIES TO STONE-BREAKERS OF PAKURH (BIHAR)

1270. SHRI J. P. YADAV :
SHRI N. K. SHEJWALKAR :
SHRI MAN SINGH VARMA :

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to provide special facilities, similar to those provided to miners, to over thirty thousand stone-breakers working in the quarry of Pakurh (Bihar) by making some provision under the Labour Laws; and

(b) if so, what are those facilities proposed to be provided to these workes ?]

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) और (ख) कुछ खान उद्योगों, जिनमें पत्थर-खानें भी शामिल हैं, में नियोजित श्रमिकों के कल्याण के लिए एक सामान्य कल्याण निधि स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारशें प्राप्त होते ही विचार किया जायेगा ।

†[THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI JAISUKHLAL HATHI) : (a) and (b) The proposal to set up a Common Welfare Fund for the welfare of labour employed in certain mining industries which *inter alia* include stone quarries also will be examined as soon as the recommendations of the National Commission on Labour become available.]

‡सुपर फास्फेट का आयात

992. **श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार 1,75,000 टन सुपर फास्फेट खाद का आयात करने का विचार रखती है, जबकि सुपर फास्फेट खाद कारखाना, उदयपुर (हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड) अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि वहां बड़ी मात्रा में सुपर फास्फेट खाद जमा हो गया है ?

†[‡IMPORT OF SUPER PHOSPHATE

992. SHRI D. THENGARI: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state whether it is a fact that Government propose to import, 1,75,000 tons of super-phosphate fertilizer whereas the phosphate fertilizer factory at Udaipur (Hindustan Zinc Ltd.,) is not working to its full capacity because large quantities of super-phosphate fertilizer have accumulated there ?]

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिंदे) : सुपर फास्फेट या फास्फेटिक उर्वरकों का आयात नहीं हो रहा है । परन्तु मांग और देशी उत्पादन के अन्तर को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष नाईट्रोजन और फास्फेटों (पी$_2$ओ$_5$) युक्त कम्पलैक्स उर्वरकों का आयात किया जा रहा है । अनुमान है कि 1968-69 की अवधि में 3,20,000 मीटरी टन पी$_2$ओ$_5$ के कुल प्रत्याशित उत्पादन की तुलना में पी$_2$ओ$_5$ की खपत का लक्ष्य 6,50,000 मीटरी टन है । शेष 3,30,000 मीटरी टन पी$_2$ओ$_5$ आयात द्वारा पूरा किया जायेगा । तथापि स्थानीय विनिर्माताओं के पास फास्फेटिक उर्वरकों के स्टाक इकट्ठे हो जाने के कारण, पी$_2$ओ$_5$ के आयात को केवल 1,36,000 मीटरी टन तक सीमित कर दिया गया है ।

हिंदुस्थान जिंक लिमिटेड की उत्पादन क्षमता केवल 12,750 मीटरी टन पी$_2$ओ$_5$ है अर्थात् कुल देशी उत्पादन का लगभग 4 प्रतिशत है । फैक्टरी में 19,000 मीटरी टन सिंगल सुपर-फास्फेट का स्टाक इकट्ठा हो गया है । सरकार ने इस स्टाक तथा भावी उत्पादन के निपटारे के लिये फैक्टरी की सहायता करने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHEB SHINDE) : No imports of superphosphate as such or straight phosphatic fertilizers are being made. Imports of complex fertilisers containing both Nitrogen and Phosphates (P_2O_5) are, however, being made every year to meet the gap between requirements and

‡Transfered from the 13th August, 1968.

†[ ] English translation.